विचार बिन्दु

एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। न वह टूटता है और न उसमें रहने वाला कभी दुःखी होता है। –अज्ञात

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोज़गार परिदृश्य

इन दिनों भारत के पढ़े लिखे तबके में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की चर्चा खूब हो रही है। जो तकनीक सक्षम हैं वे तरह-तरह से इसका प्रयोग कर रहे हैं और उनकी चर्चाओं में इसकी अपार क्षमताओं की बातें होती हैं। हरेक अपने अनुभव साझा करता है और भविष्य की कल्पनाएं भी करता है कि तकनीक के इस करिश्मे से और क्या-क्या हो सकेगा। साहित्य की दुनिया में हर मुद्दे को लपक कर हास्य व्यंग्य के मैदान में खींच ले जाने वाले महारथी इस मानवीय करिश्मे की हास्यास्पद चर्चाएं करके खुश हैं। उन्हें एक नया विषय मिल गया जिसे वे उस समय तक चींथते रहेंगे जब तक कि उन्हें कोई और नया विषय नहीं मिल जाता। वैसे सारे हास्य व्यंग्यकार ऐसा कर रहे हैं, यह मान लेना ग़लत होगा। बहुतों ने इसका बेहतरीन उपयोग भी किया है, पर वे हैं अल्पमत में। हमारे समाज का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो हालांकि इस तकनीक के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता है लेकिन सुनी-सुनाई बातों के आधार पर निष्कर्ष निकालने का अभ्यस्त है और इसी अभ्यास के चलते वह इस बात से भयभीत है कि यह नई तकनीक देश (और दुनिया) में बेरोज़गारी की सुनामी ले आएगी। उनके भय को देखते हुए लगता है जैसे बस, कुछ ही समय में सारी आबादी बेरोज़गार हो जाएगी।

वैसे, इस तरह की आशंका कोई नई बात नहीं है। जब भी नया कुछ आता है हम भयभीत हो उठते हैं। 19वीं शताब्दी में जब मशीनें आईं तो उन्होंने हाथ से काम करने वालों को प्रभावित किया। यह तो बहुत ताज़ा बात है कि जब भारत में कम्प्यूटर आया तो तत्कालीन प्रतिपक्ष ने (जो आज सत्ता में है) इसका प्रबल विरोध किया था, और विरोध का तर्क यही था कि इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी। इस बात को मान भी लिया जाना चाहिए कि जब भी नया कुछ आता है उसका असर पड़ता ही है। कम्प्यूटर के साथ डेस्कटॉप पब्लिशिंग भी आया और उसने उन कम्पोज़ीटरों को बेरोज़गार कर दिया जो हाथ से कम्पोज़ किया करते थे। बैंकों ने एटीएम लगाए तो बहुत सारे कर्मचारियों की छंटनी हो गई। एक समय था जब हर कस्बे और शहर में कैसेट्स में गाने भरकर देने वाली दुकानें हुआ करती थीं। फिर वह समय आया जब एसटीडी बूथ खूब खुले। फिर मोबाइल रिचार्ज करने वालों ने अच्छी कमाई की। एक-एक करके ये सारे धंधे ख़त्म हुए। निश्चय ही इसका असर उन लोगों पर पड़ा होगा जो इन कामों से पैसा कमा रहे थे। लेकिन हम यह कैसे भूल सकते हैं कि एक व्यवसाय ख़त्म होता है तो दो नए व्यवसाय पैदा भी होते हैं। बस, जो लोग नए व्यवसाय के लिए तैयार होते हैं वे तुरंत एक वाहन से उतर कर दूसरे में सवार हो जाते हैं, और जो तैयार नहीं होते हैं वे बेरोज़ागारी के शिकार हो जाते हैं।

कृत्रिम बुद्धि के कारण रोज़गार के नए अवसर बढ़ेंगे या बेरोज़गारी फैलेगी – इन सवालों का कोई दो टूक उत्तर नहीं हो सकता है। असल में यह बहुत जटिल मामला है। सारी दुनिया में इस पर गंभीर अध्ययन और विमर्श चल रहा है। विश्व आर्थिक मंच की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार सन 2030 तक वैश्विक श्रम बाज़ार में बड़े बदलाव आ सकते हैं। इन बदलावों के चलते तकनीकी प्रगति विशेष रूप से एआई, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन नौकरियों के सृजन और विकास दोनों को प्रभावित करेंगे। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि एआई और बिग डेटा जैसे कौशल तेज़ी से बढ़ने वाले क्षेत्र होंगे जबकि प्रशासनिक और क्लर्कीय भूमिकाएं घट सकती हैं। गोल्डन सैक्स की एक रिपोर्ट कहती है कि एआई वैश्विक स्तर पर 300 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों को प्रभावित कर सकती है और अमरीका और यूरोप में काम के एक चौथाई हिस्से को ऑटोमेट कर सकती है। मैकिंसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट कहती है कि सन 2030 तक एआई कम से कम 14 प्रतिशत वैश्विक कर्मचारियों के लिए उनका कैरियर बदलने की ज़रूरत पैदा कर सकती है। लेकिन इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एआई नए क्षेत्रों में लाखों नौकरियां सृजित भी करेगी। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि एआई और ऑटोमेशन 2028 तक विश्व स्तर पर 69 मिलियन नई नौकरियां सृजित करेंगे। मंच की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और वित्तीय क्षेत्रों में एआई के कारण डायग्नोस्टिक्स, व्यक्तिगत शिक्षा और फ्रॉडडिटेक्शन जैसे कामों में सुधार हो रहा है और इस कारण नए जॉब सृजित हो रहे हैं। मैकिंसे की रिपोर्ट में बताया गया है कि एआई से 4.4. ट्रिलियन डॉलर की अतिरिक्त उत्पादकता वृद्धि हो सकती है। लेकिन पूरी तस्वीर इतनी भी मोहक नहीं है। अगर हम यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की 2025 की रिपोर्ट देखें तो वहां यह जानकारी मिलती है कि एआई कुछ व्यवसायों में बेशक उत्पादकता और रोज़गार बढ़ाएगी लेकिन कम्प्यूटर, कानूनी व्यवसाय और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में रोज़गार वृद्धि को कम या सीमित भी कर सकती है। एक अन्य अध्ययन में यह डरावनी बात भी कही गई है कि जब एआई किसी जॉब के अधिकांश कार्यों को सम्हाल लेती है तो उस भूमिका में कर्मचारियों की संख्या 14 प्रतिशत तक कम हो सकती है।

इन सारी रिपोर्ट्स का सार यह है कि एआई का असर रोज़गार पर पड़ना निश्चित है। कुछ रोज़गारों के चेहरे बदलेंगे, कुछ नए रोज़गार पैदा होंगे और कुछ लोग बेरोज़गार भी होंगे। यह असर विकसित देशों में कम होगा क्योंकि वे तकनीक सक्षम हैं और उनके यहां शिक्षा के हालत बेहतर हैं, लेकिन इस बदलाव का असर विकासशील देशों के रोज़गार पर ज़्यादा पड़ेगा।

इन सारी रिपोर्ट्स का सार यह है कि एआई का असर रोज़गार पर पड़ना निश्चित है। कुछ रोज़गारों के चेहरे बदलेंगे, कुछ नए रोज़गार पैदा होंगे और कुछ लोग बेरोज़गार भी होंगे। यह असर विकसित देशों में कम होगा क्योंकि वे तकनीक सक्षम हैं और उनके यहां शिक्षा के हालत बेहतर हैं, लेकिन इस बदलाव का असर विकासशील देशों के रोज़गार पर ज़्यादा पड़ेगा।

अब हम थोड़ी चर्चा भारत की भी करें। गोल्ड्मैनसैक्स की रिपोर्ट कहती है कि 2027 तक भारत का एआई सेक्टर 2.3 मिलियन से अधिक नौकरियां पैदा कर सकता है, लेकिन उपलब्ध प्रतिभा पूल केवल 1.2 मिलियन तक ही पहुंच सकता है इस कारण 1 मिलियन से अधिक प्रतिभा की ज़रूरत बनी रह सकती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि रोज़गार तो होंगे लेकिन उनको कर सकने योग्य लोग हमारे पास नहीं होंगे। स्वभावतः जिन्हें रोज़गार की तलाश है, समुचित प्रशिक्षण न होने से वे बेरोज़गार रह जाएंगे। बहुत सारे अध्ययनों ने यह बताया है कि भारत में एआई की वजह से खूब नई नौकरियां उत्पन्न होंगी। जैसे यही देखें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार के अनुसार भारत में एआई के कारण सन 2030 तक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 1 मिलियन नई नौकरियां पैदा होंगी। इसी तरह मैकिंसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अनुमान के अनुसार सन 20235 तक एआई भारत पर 15.7 ट्रिलियन का प्रभाव डालेगा और 2025 तक आईटी सेक्टर में एआई से सम्बद्ध 1 मिलियन नौकरियां पैदा होंगी।

लेकिन अगर आप इससे यह समझ रहे हैं कि तस्वीर बहुत खुशनुमा है तो यह भी जान लीजिए कि टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कम्पनियों ने 2024-25 में 60 हज़ार से ज़्यादा कर्मचारियों की छंटनी की है और इसका मुख्य कारण एआई है। अर्न्स्ट एण्ड यंग (ईवाय) की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय आईटी सेवा कम्पनियां मुख्यतः एआई और ऑटोमेशन के कारण एण्ट्री लेवल भूमिकाओं में 20 से 25 प्रतिशत की कमी कर रही हैं। गोल्डमैन सैक्स ने भी चेताया है कि एआई 300 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों को प्रभावित कर सकती है और भारत में सन 2030 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 60 मिलियन जॉब्स विस्थापित हो सकते हैं।

असल में भारत का संकट यह है कि हमारे यहां रोज़गार की सम्भावनाएं तो हैं लेकिन उन सम्भावनाओं को लपक लेने की क्षमता वाले कार्मिकों का अभाव है। ईवाय की रिपोर्ट ने ठीक कहा है कि भारत की बड़ी चुनौती टेलेण्टशॉर्टेज है। हमारे केवल 3 प्रतिशत उद्यमों के पास जेनएआई के लिए इन हाउस विशेषज्ञता है और शेष 97 प्रतिशत कर्मचारी टेलेण्ट की कमी के शिकार हैं। ईवाय के अनुसार केवल 51.3 प्रतिशत कॉलेज छात्र नौकरी के काबिल हैं। इससे स्किलगैप बढ़ रहा है।

ये सारे तथ्य बताते हैं कि दुनिया के विकसित देशों की तुलना में भारत के लिए एआई की चुनौती अधिक भयावह है। हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को अद्यतन और बेहतर बना कर इस चुनौती को अवसर में भी तब्दील कर सकते हैं। रोज़गार बहुत हैं, ज़रूरत उनकी है जो रोज़गार की अपेक्षाओं पर खरे उतर सकें। अगर हमारे नीति निर्माता शिक्षा के क्षेत्र में अपने अतीतोन्मुखी एजेण्डा को लागू करने का मोह छोड़ कर उसे भविष्योन्मुखी शक्ल में ढाल सकें तो एआई हमारे लिए एक वरदान साबित होगी। इण्डिया एआई मिशन और नीति आयोग के रोडमैप जॉब क्रिएशन को पूरी ईमानदारी से सक्रिय बनाए रखकर हम अपने युवाओं के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर सके तो भारत दुनिया का एआई हब भी बन सकता है। बस, ज़रूरत है शिक्षा, निवेश और नैतिक फ्रेमवर्क की।

–अतिथि संपादक
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

जनगणना : 2001 बनाम 2027 आपदा में अवसर : चुनावी चक्कर

राम निवास बैरवा

'आपदा में अवसर' का नारा कोविड महामारी के समय से ही काफी प्रचलित रहा है- अब इसका मतलब लाशों में जीवित व्यक्तियों को ढूंढना हो या लाशों पर महल बनाना हो।

2020 की उस महामारी के चलते 2021 की प्रस्तावित जनगणना को स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद 'जातिगत जनगणना' सामाजिक सांखिकी की दृष्टि से कम और राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा प्रचारित की गयी थी। दस वर्षीय आम जनगणना सामाजिक सांख्यिकी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान 1941 की जनगणना को स्थगित नहीं किया गया था, लेकिन 2021 की आम जनगणना जो कि कोविड प्रकोप के एक साल बाद की जानी थी, को स्थगित कर दिया गया था- वह भी एक प्रकार की आपदा थी?

मैंने 2013 में "इंडिया, देट इज भारत- संवैधानिक भारत- एक समीक्षा" नामक पुस्तक प्रकाशित करवायी थी। उसमें संविधान के अनुच्छेद 81 का संदर्भ देते हुए लिखा था- "...अनुच्छेद 81 को लगातार संशाधित करके संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधि सदस्यों की संख्या फिलहाल 60 वर्षों के लिए (1971-2031 तक) सीमित कर दी गयी है, जबकि मूल प्रावधान पांच से साढ़े सात लाख की जनसंख्या पर एक लोकसभा के सदस्य के हिसाब से प्रतिनिधित्व देना था।" इसका मतलब अनुच्छेद 81 (3) के परन्तुक के अनुसार सन् 2026 के बाद की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद लोकसभा के चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन किया जाना निश्चित था, यानि कि 2031 की जनगणना के बाद 2032-33 में ही उक्त परिसीमन संभव होता।

लेकिन, 2031 की जनगणना के बाद 2032-33 तक परिसीमन का इन्तजार क्यों किया जाये, सत्ता पर अधिकार की निरन्तरता दांव पर लगी हो? इसलिए 2034, के सम्भावित लोकसभा चुनावों के पहले 2029 के संभावित लोकसभा चुनावों से पहले ही क्यों ना चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन कर दिया जाये। अगर 2021 में जनगणना करवाई जाती तो लोकसभा चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन 2032-33 में ही संभव हो पाता। इसीलिए 2021 की आम जनगणना नहीं करवाई गई। 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों को देखते हुए यह तय किया गया कि 2031 से पहले ही आम जनगणना करवा ली जाये ताकि 2029 के चुनावों से पहले ही लोकसभा के चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन कर दिया जाये। इस का परिणाम यह होना तय है कि जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश जैसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के हिस्से में लोकसभा के चुनावी क्षेत्रों की संख्या अधिक आयेगी। इसकी तुलना में दक्षिण भारत के राज्यों के हिस्से में लोकसभा की कम सीटें मिलेंगी। इसका परिणाम यह होगा कि लोकसभा में उत्तरी भारत के राज्यों को ज्यादा सीटें मिलने से सरकार में उन्हीं का वर्चस्व रहेगा। इसी प्रकार की शंका तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रकट की है।

भारत के वर्तमान चुनावी लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों से इमानदार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की उम्मीद करना व्यर्थ है। जिसको भी मौका मिलता है, लाशों में से जीवित व्यक्तियों का बचाने के बदले लाशों पर अपने-अपने महल बनाने की सूझती है।

अनुच्छेद 81 (3) में इस प्रकार की सीमा निर्धारित करने वाला प्रावधान परन्तुक 1976 के 42वें संविधान के द्वारा जोड़ा गया था। तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस सरकार की चुनावी प्राथमिकताओं को उस समय जारी अपातकाल से लगाया जा सकता है। कांग्रेस के ही युवा प्रधानमंत्री के द्वारा युवाओं को अपनी चुनावी प्राथमिकता मान कर मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष की गई। लेकिन, उन्हीं युवाओं ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। 2001 में तीन बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना चुके अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावी क्षेत्रों के परिसीमन के वर्षों को अलग-अलग करके लोकसभा के लिए वर्ष 2026 के बाद की जनगणना और विधानसभाओं के चुनावी क्षेत्रों की परिसीमन के लिए 2001 की जनगणना को आधार बनाया था।

तद्नुसार, 2001 की जनगणना के आधार पर विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया गया- लेकिन इमानदारी उसमें भी नहीं बरती गई उदाहरण के लिए राजस्थान के जयपुर शहर के विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया जिसमें आठ (8) विधानसभा क्षेत्र बनाये गये। चूंकि 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के अनुसार जयपुर शहर की आठ विधानसभा क्षेत्रों में से एक अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्योंकि जयपुर शहर के सभी धुरंधर दावेदार सामान्य वर्गों से रहे है, अतः बड़ी ही चालाकी से काम लेते हुए जयपुर शहर दो टापूनुमा इलाके अनुसूचित जाति के लिए छोड़े गये और उनकी जनसंख्या कम होने के कारण उन्हें जयपुर ग्रामीण के बगरू विधानसभा में जोड़ गया। इसका परिणाम यह रहा कि बगरू विधानसभा क्षेत्र की सीमाएं तीन टापुओं जैसे इलाकों में बंटा है। उनके बीच में आने वाले एकीकृत सीमाओं के जोहरी बाजार और सांगानेर विधानसभा क्षेत्र पड़ते है- जबकि बगरू विधानसभा क्षेत्र में बगरू के ग्रामीण इलाकों के अलावा जयपुर शहर के सांगानेर के कुछ इलाके, वाटिका इलाके का कुछ भाग तथा जयपुर शहर के दक्षिण पूर्व के कुछ इलाके शामिल है। इस प्रकार के परिसीमन नितांत षड्यंत्रकारी है- लोकतान्त्रिक ईमानदारी ऐसी कार्रवाइयों में कहीं भी दिखाई नहीं देती। 2029 के लोकसभा चुनावों के पहले लोकसभा चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का प्रयास इस तरह के बहुत सारे राजनीतिक दुराचरणों की संभावनाओं का बखान करते हैं। यहीं आपदा में अवसर की तलाश हैं।

–राम निवास बैरवा,
पूर्व क्षेत्रिय भविष्यनिधि आयुक्त

राज्य विश्वविद्यालय: वित्तीय विपन्नता और नैतिक पतन के बीच झूलता भविष्य

प्रो. अशोक कुमार

आज भारत के राज्य विश्वविद्यालय एक दोराहे पर खड़े हैं। एक ओर वे गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जहाँ सरकारें हाथ खींच रही हैं और छात्र ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की ओर पलायन कर रहे हैं। दूसरी ओर, जो संस्थान बचे हुए हैं, वे पद के मद और प्रशासनिक कुप्रबंधन की भेंट चढ़ रहे हैं। प्रश्न केवल यह नहीं है कि विश्वविद्यालयों के पास पैसा क्यों नहीं है, बल्कि प्रश्न यह भी है कि जो नेतृत्व इन संस्थानों को दिशा देने के लिए बैठा है, उसकी दृष्टि और व्यवहार कैसा है?

विश्वविद्यालय का प्रमुख कुलपति होता है, जिसे कुलगुरु की संज्ञा दी गई है। परंपरा के अनुसार, इस पद पर आसीन व्यक्ति को ज्ञान, शालीनता और धैर्य का प्रतीक होना चाहिए। किंतु, हाल ही में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में हुई घटना-जहाँ एक कुलपति ने आमंत्रित अतिथि साहित्यकार को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर बाहर जाने को कह दिया-एक भयावह सत्य उजागर करती है। रहीम का वह दोहा-जो रहीम ओछो बढ़े, तौ अति ही इतराय-आज के कई कुलपतियों पर सटीक बैठता है। जब छोटे व्यक्तित्व के लोग राजनीति या सिफारिश के बल पर ऊँचे पदों पर पहुँच जाते हैं, तो उनमें विनम्रता के स्थान पर अहंकार का जन्म होता है। वे भूल जाते हैं कि विश्वविद्यालय ईंट-गारे की इमारत नहीं, बल्कि विचारों के आदान-प्रदान का एक जीवंत मंच है।

कुलपतियों का वर्गीकरण: पतन के विभिन्न रूप

राष्ट्रदूत मे प्रकाशित लेख मे प्रो. अशोक कुमार ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पाँच श्रेणियों में विभाजित कर इस पतन की जड़ को स्पष्ट किया है:

राजनीतिक कुलपति: इनका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय का विकास नहीं, बल्कि अपने राजनैतिक आकाओं को खुश करना और उनके एजेंडे को लागू करना होता है। इससे संस्थान की निष्पक्षता समाप्त हो जाती है।

रिश्वतखोर कुलपति: ये वे लोग हैं जो धन या प्रभाव के बल पर कुर्सी हासिल करते हैं। इनका पूरा ध्यान विश्वविद्यालय के संसाधनों का दोहन कर अपना निवेश वसूलने पर होता है।

प्रशासकीय एवं शैक्षणिक कुलपति: एक आदर्श कुलपति को इन दोनों गुणों का मिश्रण होना चाहिए। उसे न केवल कागजी कार्यवाही में दक्ष होना चाहिए, बल्कि उसमें छात्रों और शिक्षकों के लिए एक प्रेरक वातावरण बनाने की दृष्टि भी होनी चाहिए।

सामाजिक कुलपति: जो विश्वविद्यालय को समाज से जोड़ सकें। दुर्भाग्यवश, आज के कुलपति अक्सर बंद कमरों में बैठकर आदेश जारी करने वाले तानाशाह बन गए हैं।

विश्वविद्यालयों की बदहाली का एक बड़ा कारण वित्तीय सहायता की कमी है। जब सरकारें शिक्षा को निवेश के बजाय खर्च मानने लगती हैं, तो बजट में कटौती होने लगती है। इसका सीधा असर प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और शोध पर पड़ता है।

जब छात्रों को दिखता है कि विश्वविद्यालय में न तो नियमित कक्षाएं लग रही हैं, न ही वहां का माहौल उनके बौद्धिक विकास के लिए अनुकूल है, तो वे ऑनलाइन कोर्सेज या कोचिंग संस्थानों की ओर रुख करते हैं। ऑनलाइन शिक्षा उन्हें कम से कम डिठ्ठी और स्किल तो दे रही है, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन केवल अहंकार और अव्यवस्था का केंद्र बनकर रह गया है। विश्वविद्यालयों का मूल उद्देश्य छात्रों को प्रश्न पूछना सिखाना है। कबीरदास ने कहा था- निंदक नियरे राखिए-अर्थात आलोचना करने वाले को अपने पास रखें। लेकिन आज की स्थिति इसके विपरीत है। यदि कोई शिक्षक या छात्र प्रशासन की गलत नीतियों पर सवाल उठाता है, तो उसे अनुशासनहीनता के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। बिलासपुर की घटना में कुलपति का यह पूछना कि "क्या आप मेरी बातों से बोर हो रहे हैं?" और फिर असहमत व्यक्ति को बाहर निकालना, बौद्धिक तानाशाही का चरम है। यह विचार कि विश्वविद्यालयों को बंद कर कोचिंग संस्थान खोल देने चाहिए, आत्मघाती है। कोचिंग संस्थान केवल परीक्षा पास करना सिखाते हैं, वे नागरिक बनाना नहीं सिखाते। वे शोध नहीं करते, वे साहित्य और कला का सृजन नहीं करते। समाधान विश्वविद्यालयों को बंद करने में नहीं, बल्कि उन्हें साफ करने में सुधार का मार्ग: समाज की भूमिका

समाज का मौन रहना बुराई को फलने-फूलने का मौका देता है। भीष्म पितामह का उदाहरण देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग अधर्म या दुर्व्यवहार को देखकर चुप रहते हैं, इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करता।

प्रबुद्ध वर्ग की जिम्मेदारी: लेखकों, पत्रकारों और नागरिक समाज को इन संस्थानों में हो रहे नैतिक पतन के खिलाफ आवाज उठानी होगी।

नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव: कुलपतियों की नियुक्ति पूरी तरह से गैर-राजनीतिक और पारदर्शी होनी चाहिए। केवल वे ही इस पद पर बैठें जिनके पास शैक्षिणक गरिमा और प्रशासनिक सूझबूझ हो।

जवाबदेही तय करना: किसी भी कुलपति को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह अपने पद का दुरुपयोग कर किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाए।

निष्कर्ष-- भारतीय विश्वविद्यालय आज केवल धन की कमी से नहीं, बल्कि चरित्र की कमी से मर रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि भारत विश्वगुरु बने, तो हमें पहले अपने विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं को सुधारना होगा। संस्थानों को बचाने के लिए फंड से अधिक नैतिकता और संवाद की आवश्यकता है। हमें ऐसे विश्वविद्यालयों की जरूरत है जहाँ असहमति का सम्मान हो, न कि जहाँ सवाल पूछने पर बाहर का रास्ता दिखाया जाए।

–प्रो. अशोक कुमार,
विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

भीलवाड़ा : कोठारी नदी में अवैध बजरी से भरे नौ ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के रायपुर थाना क्षेत्र में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस ने अब तक की एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस प्रशासन ने बीती रात कोठारी नदी में छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे नौ ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। इस दौरान पुलिस ने खनन माफियाओं में हड़कंप मचाते हुए सात लोगों को गिरफ्तार भी किया है।

जानकारी के अनुसार अवैध बजरी खनन और परिवहन पर नकेल कसते हुए, रायपुर पुलिस ने शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। डिप्टी सदर माधव उपाध्याय के नेतृत्व में यह कार्रवाई रायपुर थाना क्षेत्र के पनोतिया और नाथडियास गांव के बीच कोठारी नदी में की गई। पुलिस को मुखबिर से लगातार

■ पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया

सूचना मिल रही थी कि इस क्षेत्र में रात के अंधेरे में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। सूचना पक्की होते ही पुलिस टीम ने नदी क्षेत्र में दबिश दी। मौके पर पुलिस ने बजरी से भरे हुए 9 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त किया। साथ ही, अवैध खनन और परिवहन में शामिल सात लोगों को मौके से ही धर दबोचा गया। माधव उपाध्याय ने बताया कि सभी जब्त ट्रैक्टरों को रायपुर थाने में खड़ा करवाया है और खनिज विभाग को सूचित कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ यह अभियान थमने वाला नहीं है और भविष्य में भी ऐसी सख्त कार्यवाही जारी रहेगी।

अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली को रायपुर थाने में खड़ा करवाया।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

सोमवार 9 फरवरी, 2026

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, सोमवार, विक्रम संवत 2082, विशाखा नक्षत्र मंगलवार प्रातः 7:55 तक, वृद्धि योग रात्रि 12:52 तक, बालव करण सायं 6:15 तक, चन्द्रमा रात्रि 1:11 से वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-तुला, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-कुम्भ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज यमघट योग सूर्योदय से सम्पूर्ण दिन-रात है। आज कालाष्टमी जानकी जयन्ती है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 8:34 तक, शुभ 9:56 से 11:19 तक, चर 2:03 से 3:25 तक, लाभ-अमृत 3:25 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 7:12, सूर्यास्त 6:10

मेष
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं, उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा।

वृष
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

कर्क
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

सिंह
व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।

तुला
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है।

धनु
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

मकर
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
नवीन कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है।

मीन
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।